बड़ी सफलता

दैनिक जागरण, 13-4-15

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की सफल यात्रा के बाद इसकी उम्मीद बढ़ गई है कि उन्हें ऐसी ही सफलता जर्मनी और कनाडा में भी मिलेगी। भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि भारत सरकार ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया, बल्कि इसलिए भी है कि वहां की कई कंपनियों ने मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियान में सहयोग देने के लिए हामी भरी। इस सबके अतिरिक्त यह स्पष्ट ही है कि विभिन्न क्षेत्रों में 17 समझौतों के साथ फ्रांस और भारत में मित्रता और प्रगाढ़ होती हुई दिखी। यूरोप के शक्तिशाली देशों में गिने जाने वाले फ्रांस में भारतीय प्रधानमंत्री को जिस तरह हाथों हाथ लिया गया और वहां के मीडिया ने भी उसे प्रमुखता प्रदान की उससे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कद का पता चलता है। फ्रांसीसी कंपनी दासौ से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला लंबे समय से अटका हुआ है। पिछली सरकार ने इन विमानों को खरीदने के लिए दासौ से बातचीत का जो सिलसिला शुरू किया था वह अभी भी कायम है। यह कहना कठिन है कि यह सिलसिला कब जाकर थमेगा और विमान सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकेगा, लेकिन यह सुखद है कि भारतीय वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने सीधे फ्रांस सरकार से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद दो साल के अंदर ही भारत को ये लड़ाकू विमान मिल जाएंगे।

विमान खरीदने के इस फैसले को लेकर कांग्रेस की ओर से कुछ सवाल उठाए गए, लेकिन वे महज विरोध के लिए विरोध की राजनीति का उदाहरण भर हैं। इस सौदे की आलोचना करने वाले इस तथ्य को ध्यान में रखें तो अच्छा है कि पिछले करीब 17 सालों से भारत ने लड़ाकू विमान नहीं खरीदे हैं और इसके चलते भारतीय वायुसेना को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लड़ाकू बेड़े में शामिल तमाम विमान पुराने पड़ चुके हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी इस्तेमाल की अवधि पूरी होने के करीब है। इन स्थितियों में यह आवश्यक था कि भारतीय वायुसेना नए लड़ाकू विमानों से लैस हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि राफेल विमान खरीद के इस सौदे के साथ ही कुछ पुराने सौदों को भी गति मिलेगी। यह अजीब बात है कि रक्षा जरूरतों को पूरा करने के काम में भी इतनी अधिक देरी होती है। ऐसा कोई तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है जिससे जरूरी रक्षा खरीद अनावश्यक न खिंचने पाए। चूंकि इन विमानों की खरीद के साथ ही यह भी फैसला हुआ कि संबंधित विमान कंपनी अपने विमानों का निर्माण भारत में करने की संभावना भी टटोलेगी इसलिए मेक इन इंडिया अभियान को भी बल मिल सकता है। वैसे भी एक अन्य विमान कंपनी एयरबस तो इस अभियान में सहयोग देने के लिए तैयार भी है। कुछ अन्य फ्रांसीसी कंपनियां भी मेक इन इंडिया अभियान में शामिल होने जा रही हैं। अच्छा यह होगा कि फ्रांस के साथ जो समझौते हुए उन पर अमल की प्रक्रिया को गति देने की भी कोई व्यवस्था बनाई जाए। ऐसा इसलिए, क्योंकि विभिन्न देशों से जो समझौते होते हैं वे कई बार कार्यरूप में परिणत होने में वर्षो का समय ले लेते हैं।

प्राथमिक शिक्षा में समानता के साथ दोहरी कामयाबी

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने ऐसी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसकी तरफ आमतौर पर ध्यान नहीं दिया गया है, मगर इसे यूनेस्को ने दर्ज किया है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में स्कूलों में दाखिला करवाने और लड़के-लड़कियों का फासला मिटाने में शानदार प्रगति के लिए जिन देशों की तारीफ की, उनमें भारत भी है। साल 2000 में 'सबके लिए शिक्षा' के लक्ष्य पर 164 देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहमति हुई थी। उस पर अमल में विभिन्न देश कितना आगे बढ़े, यूनेस्को ने इसी की समीक्षा की है। इसके मुताबिक प्राइमरी स्कूल स्तर पर भारत में तकरीबन 99 प्रतिशत बच्चों का दाखिला हो रहा है। खास बात यह है कि इनमें लड़के और लड़कियों की संख्या समान है यानी दोहरी कामयाबी। कई दूसरी रिपोर्टों ने भी पुष्टि की है कि मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू होने के बाद से 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के स्कूल जाने में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसमें बड़ी भूमिका मध्याह्न भोजन योजना की भी है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि मध्याह्न भोजन योजना भी इस ढंग से लागू की जा रही है कि वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। यह दीगर बात है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल कायम हैं, जिसका जिक्र यूनेस्को ने भी किया है। बहरहाल, एक कामयाबी से दूसरी सफलता की दिशा में बढ़ने का रास्ता साफ होता है। अपेक्षा है कि अब सरकारें पढ़ाई-लिखाई का स्तर सुधारने पर यथोचित ध्यान देंगी। फिलहाल, यह गर्व की बात है कि भारत में आरंभिक शिक्षा में लैंगिक समता प्राप्त कर ली गई है। यह प्रगति तब और बड़ी लगती है, जब हम यूनेस्को की रिपोर्ट के दूसरे हिस्सों पर गौर करते हैं। इसके मुताबिक लगभग आधे देश ही सभी बच्चों को प्राइमरी स्कूलों तक लाने में सफल हुए। कई देशों ने लड़कों के मामले में ऐसा किया, मगर लड़कियों के मामले में पिछड़े हुए हैं। यानी लड़के व लड़कियों में फर्क यह वैश्विक स्तर की समस्या है। गौरतलब है कि साल 2000 में तय एजेंडे में छह लक्ष्य थे, जिन पर पूरी प्रगति सिर्फ एक तिहाई देशों ने की है। इनमें प्रेप (प्राइमरी शिक्षा से पहले) स्तर पर सभी बच्चों का दाखिला, उनकी पूरी देखभाल, माध्यमिक स्तर पर भी लैंगिक समता लाने और वयस्क साक्षरता के मामलों में भारत को भी अभी काफी कुछ करना है। मगर यह निर्विवाद है कि अपने देश ने ज्ञान का उजाला सब तक पहुंचने की दिशा में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया है।